

superannuation to the employees of the Heavy Engineering Corporation Ltd., Ranchi; and

(b) the details of all such cases giving periods of extension and the reasons for allowing such extensions?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) and (b). Extension after the date of superannuation has not been allowed to any of the regular employees of the Company. After superannuation from Government Service, 4 officers were appointed in the company as Deputy Controller of Shipping (Claims), Law Officer, Deputy Controller (Movement) and Town Administrator. The first 3 officers have been granted extension till September, 1967 and the last officer till June, 1968. In view of the nature of work handled by them and their experience and suitability the extensions granted were considered necessary.

समुदाय द्वारा कुछ उच्चतकनिक उत्पादों पर दी गई टैरिफ रियायतों का उपयोग करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की गई है। इसी प्रकार अन्य सुविधाओं, जैसे व्यापारिक भेदों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेने की सुविधाओं और भारत के उत्पादों की बिक्री के लिये तकनीकी सहायता का यथासम्भव अधिकतम उपयोग किया जा रहा है।

(ख) ऐसा कोई उदाहरण नहीं है।

(ग) भारत से निर्यात किये जाने वाले उत्पादों पर यूरोपीय अधिक समुदाय द्वारा दी गई रियायतें निम्न प्रकार हैं :—

	लाख ₹०
1963	480
1964	537
1965	511
1966	437

यूरोपीय मात्सा बाजार

2719. श्री स० च० साबन्त : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय मात्सा बाजार के सदस्य देशों द्वारा भारतीय व्यापार के लिये दी गई सुविधाओं का लाभ उठाने के लिये कार्यवाही की जा रही है;

(ख) किन किन देशों ने कठिनाइयाँ पैदा की हैं जबकि जर्मनी में अपनी प्रतिष्ठा व्यक्त की है; और

(ग) यूरोपीय मात्सा बाजार के सदस्य देशों द्वारा दी गई व्यापार सुविधाओं से भारत को क्या हानि हुई है जबकि क्या लाभ हुआ है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :

(क) अप्रैल 1964 से कुत्कों को हटाने का बताने के रूप में यूरोपीय वाणिज्य

इस प्रकार 1963 से 1965 की अवधि में हमारे निर्यात में मात्सा बाजार की वृद्धि हुई है। 1966 में गिरावट के कई कारण हैं जो अधिकांशतः प्राकृतिक हैं जैसे घरेलू खपत में वृद्धि तथा उत्पादन में कमी होना।

Import of Cashewnuts

2720. Shri Mangalathumatom: Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) whether representations have been received from Cashew industrialists in Kerala for importing cashewnuts in order to run the cashew factories throughout the year; and

(b) if so, the steps taken on these representations?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh): (a) No, Sir.

(b) Import of Cashewnuts is being allowed under Open General Licence.